[श्री धर्मचन्द्र प्रशान्त]

का विचार है । पता नहीं हम लोग इसको क्यों छोड़ रहे हैं । यह चाहे राज्य सरकारें हो या केन्द्रीय सरकार हो यह उनका उत्तरदायित्व है कि संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करें । मैं मानता हूं कि केन्द्र ने संस्कृत के उत्थान के लिये बहुत कुछ किया है रुपया भी खर्च किया है । परन्तु योजना-बद्ध न होने के कारण उस की सफलता उसको नहीं मिल रही है । क्योंकि हमारे सामने कुछ वर्षों से त्रिभाषा फार्मूला आ गया है उसके अन्तर्गत वहां के विद्यार्थियों को एक तो स्थानीय भाषा पढ़नी पड़ती है, प्रादेशिक भाषा पढ़नी पड़ती है, फिर अंग्रेजी भाषा पढ़नी होती है उसके साथ एक और भाषा भी पढ़नी पड़ती है । इससे संस्कृत निकल जाती है । यही कारण हो रहा है कि संस्कृत के विद्यार्थी हर वर्ष घटते जा रहे है। आप दिल्ली को ही देख लें । दिल्ली के जो आंकड़े है उनके अनुसार यह पता चलता है कि हर वर्ष इसकी पढ़ाई नीचे जा रही है । जब तक इस त्रिभाषा फार्मूले से इस संस्कृत को न निकाला जाए और उसके लिए अलग समुचित प्रबन्ध न किया जाए तब तक संस्कृत भाषा पनप नहीं सकती उसको वह स्थान नहीं मिल सकता जो कई वर्ष पहले मिला हुआ था । संस्कृत में कई ग्रन्थ पड़े है जिनका अभी तक अनुवाद नहीं किया गया है । कम से कम तीन चार सौ नाटक होंगे जिनका अनुवाद अभी तक नहीं हुआ है । ये लाइब्रेरीज में कहीं पडे हुए हैं । हमारे जम्मू काश्मीर में एक बड़ी भारी लाइब्रेरी है जिसमें एक हस्तलिखित ग्रन्थ है इसका नाम राघव पाण्डवीयम्। यह छठी शताब्दी में लिखा गया जिसको कविराज ने लिखा । यह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसको देख कर आश्चर्य होता है कि इसका कौन लेखक होगा जिसने यह ग्रन्थ लिखा है । मैं इसे एक व्यक्ति को देता हूं और कहता हूं कि इसे पढ़िये यह रामायण है तो वह उस को रामायण के रूप में पढ़ जायेगा । दूसरे को मैं दूंगा और यह कहूंगा कि यह महाभारत है तो वह उसको महाभारत ही पढ़ जायेगा । उसमें रामायण और महाभारत को कवा विचित्र ढंग से लिखी गई है कि वह रामायण भी है और महाभारत भी । इसका मैन्युस्क्रिप्ट भोजपत्र में पड़ा हुआ है । यदि संस्कृत की यह हालत रही तो इन ग्रन्थों का क्या बनेगा । हमारे ग्रन्थ है, प्रचीन कृतियां है, कथाएं है उनका क्या होगा ? यदि संस्कृत निकली गई तो क्या होगा ? इन ग्रन्थों को बचाना है संस्कृत को बचाना है उसके लिए मैं केन्द्र सरकार से कहूंगा कि वह इसकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करे और इससे को त्रिभाषा फार्मूले से निकाले ।

श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल (मध्य प्रदेश) : संस्कृत वालों को नौकरी भी दी जाए ।

REFERENCE TO THE REPORTED QUESTION OF FERTILE LAND FOR THE DEVELOPVIENT OF NATION/VE CAPITAL REGION

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश) : अभी केन्द्रीय सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली के चारों तरफ 100 किलोमीटर सवा सौ किलोमीटर के दायरे में जो शहर स्थित है उन में से कुछ शहरों को विकसित किया जाए और आहिस्ता-आहिस्ता दिल्ली के साथ जोड़ कर एक नेशनल केपिटल रीजन बना दिया जाए । यह फैसला इस दृष्टि से किया गया है कि जिस हिसाब से लोग भाग कर दिल्ली में आ रहे हैं आबादी बढ़ेगी उन लोगों को कहीं बसाना है । मैं इस फैसले का विरोध

करता हूं। श्रीमन मेरा गांव यहां से 45 –50 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे गांव में बेहद बढ़िया किस्म की जमीन है और दिल्ली के आसपास डेढ़ सौ किलोमीटर के इलाके में नदी के आसपास एक दो किलोमीटर के स्ट्रेच को छोड़ कर बाकी बहुत उम्दा किस्म की जमीन है। अगर यह योजना लागू की गयी तो अनाज पैदा करने वाली सबसे बेहतरीन जमीनें खत्म हो जायेंगी और उनमें तमाम तरह के अनियोजित किस्म के मकान बन जायेंगे। किसानों को मुआवजा एक रुपये मिलेगा और दो हजार रुपये में वह जमीन बिकेगी। वे बेघरबार हो जायेंगे। करीब एक हजार किलोमीटर का सारा इसका इलाका बैठेगा। ये तमाम लोग उजड़ जायेंगे, खत्म हो जायेंगे। इसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है कि आज दिल्ली मैनेजेबूल नहीं है। जितनी बड़ी दिल्ली है इसके लिए दूध की किल्लत है, पानी की किल्लत है। जैसे बाहर से विजेता आता था और वह तमाम लोगों को परास्त करता हुआ जमीनों पर कब्जा करता हुआ चला जाता था वैसे ही शहर चलाने वाले लोगों का, देश के चलाने वाले लोगों का उसूल हो गया है। आप जबरदस्ती खेती की जमीन पर लोगों को बसाते चले जायेंगे। यमुना नहर सिंचाई के लिए थी उसका पानी जबरन ले लिया गया शाहदरा के लोगों को पिलाने के लिए। अगर इतनी बड़ी दिल्ली विकसित करेंगे तो फिर न पानी मिलेगा न दूध मिलेगा, न बिजली मिलेगी और अगर मिलेगी भी तो ग्रामीणों की कास्ट पर मिलेगी और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि इतना बड़ा अर्बन जंगल हो जायेगा कि उसमें क्राइम पनपेंगे, डिमारेलाइजेशन होगा और तमाम तरह की व्याधियां पैदा होंगी तथा यह करोड़ों की आबादी का सारा इलाका भ्रष्ट लोगों का, पतित लोगों का इलाका बन जायेगा। तो श्रीमन, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कम्युनिस्ट मुल्कों में है कि शहरों की एक सीमा हो गयी है कि इसके आगे शहर नहीं बनेंगे और विकास होगा तो गांवों में होगा तहसील में होगा और गांवों के नजदीक विकास नहीं होगा, सारे उद्योग धंधे शहरों में नहीं पहुंचेंगे, वैसे ही यहां भी होना चाहिए।

जब आप राजधानी के लिए ही नीति नहीं बनाएंगे तो फिर सारे देश के गांव उजड़ जायेंगे और लोग वहां से भाग जायेंगे। इसको रोका जाये और कम से कम टाउन प्लानिंग के सारे विशेषज्ञों को बुलाकर बैठकर यह तय हो कि क्या करना चाहिए। सारे रोजगार शहरों में क्यों जा रहे हैं और जिन इलाकों के लोगों से इस योजना का ताल्लुक है वहां के एम० पी० एम० एल० ए० और वहां के नुमाइंदों को बुला करके इस पर विचार किया जाये तब ही इस पर कोई कदम शुरू किया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस योजना को फिलहाल रोकें और दिल्ली की जो बढ़ती हुई बदसूरत शक्ल है इसको रोकने की कोशिश कीजिए तथा सही तरीके से टाउन प्लानिंग हो। बहुत बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI). Now, special mention by Shri Ramsinghbhai Pataliyabhai Rathvakoli—not here. Now the Messages from Lok Sabha, Yes, Mr. Secre-t'ary-General.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. The Payment of Gratuity (Amend ment) Bill, 1984.

II. The Payment of Gratuity (Second Amendment) Bill, 1984

SECRETARY-GENERAL; Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha,